NT>

Title: Need to resolve the issue regarding construction of Sutlej-Beas link canal in Punjab before establishing the national river grid for interlinking of rivers.

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, 20 नवम्बर, 2002 को देश के प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि नेशनल रिवर ग्रिड का गठन और इंटर लिंकिंग आफ रिवर किया जाएगा। यह बहुत स्वागत योग्य बात है। मैं इसमें एक बात आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा। कुछ राज्यों में इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट के मामले चल रहे हैं। कई जगह पर डैड लाइन तय की गई है कि जनवरी तक फलां-फलां रिवर की कम्प्लीशन होनी चाहिए। पंजाब इसमें एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, जिसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए।

During the Indus Water Treaty, out of six western rivers of the Punjab, three, that is, Jhelum, Chenab and Indus, were left with Pakistan and the other three, that is, Raavi, Beas and Sutlej, were with India. Now, the basic point is, अन्य राज्यों को भी पानी की जरूरत है, यह बात ठीक है। सरकार नेशनल रिवर ग्रिड बनाने की योजना पर विचार कर रही है, तो उसे विपक्ष को और सभी सांसदों को भी विश्वास में लेकर इस सम्बन्ध में एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाना चाहिए। जैसे सतलुज-व्यास लिंक नहर का मामला है। प्रधान मंत्री जी के 20 नवम्बर के बयान के बाद सतलुज-व्यास लिंक नहर का मुद्दा सुपरसीड हो गया है। दूसरी तरफ पंजाब को कहा जा रहा है कि 15 जनवरी तक वह सतलुज-व्यास लिंक नहर का निर्माण करे। ये दोनों तर्क एक साथ समझ में नहीं आते, क्योंकि यह विवादित मुद्दा है। इसलिए जो डेड लाइन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, अगर सरकार दरियाओं को लिंक करना चाहती है तो यह मामला सुपरसीड हो जाता है। इसलिए इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।